

दिनांक 17 जुलाई, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./188-84/29739.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. डयूरेवल स्पीगंस इंडिया प्रा० लि०, प्लॉट नं० 259, सैक्टर-25 फरीदाबाद के श्रमिक श्री रघुनाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उस से सुसंगत अथवा उस से संबंधित मामला है:—

क्या श्री रघुनाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है;

सं. ओ.वि./एफ.डी./118-85/29746.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. आर० एम० कन्ट्रोल प्रा० लि०, 13/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री हरी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उस से संबंधित मामला है:—

क्या श्री हरी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी./118-85/29753.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० आर० एम० कन्ट्रोल प्रा० लि०, 13/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री शत्रुघ्न राय तथा उस प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है:—

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री शत्रुघ्न राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी./118-85/29760.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. आर० एम० कन्ट्रोल प्रा० लि०, 13/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री कैलाश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री कैलाश चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 23 जुलाई, 1985

सं० ओ०वि०/एफ० डी०/72-85/30796.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है, कि मै० परफैक्ट इण्डस्ट्रीयल संजय मैमोरियल स्टेड प्लाट नं० 15, 20/2, फरीदाबाद के श्रमिक श्री गरीश चन्द्र तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/5234, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी०-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री गरीश चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 24 जुलाई, 1985

सं० ओ०वि०/हिसार/49-84/31107.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० प्रशासक नगरपालिका, हिसार, के श्रमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/अम्बाला/31114.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा हैण्डलूम वीवर्ज एपैक्स कोर्पोरेटिव सोसायटी लि०, पानीपत, के श्रमिक श्री हुकम सैन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ।

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हुकम सैन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 30 जुलाई, 1985

सं० ओ०वि०/32050.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० एस० के० गलास इण्डस्ट्रीज, प्रा. लि०, रमोई सोनीपत, के श्रमिक श्री राज सिंह चौहान तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री राज सिंह चौहान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

जे० पी० रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग ।

HARYANA
PUBLIC WORKS
(PUBLIC HEALTH

Notification

The 26th

No. 2/20/79-PH(I).—The Governor of Haryana is pleased to declare the result of Departmental

Serial No.	Name of Candidate	Water Supply and Sanitary Installation	Material and Construction	Drainage and Sewerage
		M. M. 100	M. M. 50	M. M. 50
		I	II	III
1	Shri D. S. Duhan	Fail	Passed in 12/83	Passed in 12/83
2	Shri Chander Mohan Kansal	Passed in 8/82	Passed in 8/82	Passed in 8/82
3	Shri Jai Narain	Passed in 12/83	Passed in 8/82	Pass
4	Shri Sat Pal Sharma	Fail	Fail	Pass
5	Shri B. S. Singla	Pass	Passed in 12/83	Pass
6	Shri S. K. Verma	Passed in 12/83	Fail	Passed in 2/83
7	Shri S. L. Nagpal	Fail	Fail	Passed in 2/83

MECHANICAL

Name of Candidate	Mechanical Engg.	Elements of W/S and Sewerage	Accounts and Office Procedure
	M. M. 100	M. M. 50	M. M. 50
	Paper-I	Paper-II	Paper-III
8	Shri Arvinder Singh	Pass	Passed in 7/84

Dated Chandigarh,
the 26th July, 1985.

GOVERNMENT

DEPARTMENT

BRANCH)

July, 1985

Professional Examination held from 18th February, 1985 to 20th February, 1985.

Mechanical Engineering	Accounts and. Office Procedure	General oral Examination	Remarks
M.M. 50	M.M. 100	M.M. 50	
IV	V	VI	
—	Fail	Passed in 2/83	To reappear in papers I, IV and V.
Passed in 8/82	Fail	Passed in 8/82	To reappear in paper V.
Passed in 12/83	Passed in 8/82	Passed in 12/83	Pass.
Passed in 7/84	Passed in 7/84	Pass	To reappear in papers I and II.
Passed in 8/82	Passed in 8/82	Passed in 8/82	Pass.
Passed in 8/82	Passed in 8/82	Passed in 8/82	To reappear in paper II.
Passed in 11/80	Passed in 2/83	Passed in 11/80	To reappear in papers I and II

ENGINEERS

Mtc. of Mech. and Elect.	General Oral Examination	Remarks
M.M. 50	M.M. 50	
Paper IV	Paper V	
Fail	Pass	To reappear in paper IV.

ASHOK PAHWA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
P.W.D., Public Health Branch.

सं.ओ.वि./अम्बाला/पानो/48-84/32071.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता एस. आई. कन्स्ट्रक्शन डिविजन एच.एस.ई.बी. करनाल, के श्रमिक श्री बलबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है;

क्या श्री बलबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

जे० पी० रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग ।

LABOUR DEPARTMENT

The 29th July, 1985

No. 9/5/84-6Lab./6146.—In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947) the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of Presiding Officer, Labour Court, Faridabad in respect of the dispute between the workman and the management of M/s Shiv Shankar Homoeo Pvt. Ltd., 0/3, Link Road, Faridabad.

IN THE COURT SHRI R. N. SINGAL, PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT, FARIDABAD

Reference No. 44 of 1983

between

SHRI LAL BABU BHARI, WORKMAN AND THE RESPONDENT-MANAGEMENT OF M/S. SHIV SHANKAR HOMOEOPVT. LTD, 0/3, LINK ROAD FARIDABAD

Present :—

Shri H.P. Singh, for the workman.

Shri S.N. Sharma, for the respondent-management.

AWARD

This industrial dispute between the workman Shri Lal Babu Bhari and the respondent-management of M/s. Shiv Shankar Homoeo Pvt. Ltd., 0/3 Link Road, Faridabad has been referred to this court by the Hon'ble Governor of Haryana,—vide his order No. ID/FD/225-82/694—99, dated 6th January, 1983, under Section 10(i)(c) of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication. The term of the reference are :—

Whether the termination of services of Shri Lal Babu Bhari was justified and in order? If not, to what relief is he entitled?

The representative of the workman has made a statement that he does not to pursue to this reference. Hence this reference is decided that no dispute is pending between the parties.
Dated 10th July, 1985.

R. N. SINGAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

Endst. No. 1957, dated 16th July, 1985.

Forwarded (four copies) to the Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh as required under section 15 of the Industrial Dispute Act.

R. N. SINGAL,
Presiding Officer,
Labour Court, Faridabad.

KULWANT SINGH,
Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.